Q-13016/02/2023-DISHA (E383152)
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Monitoring Division-DISHA)

Room No.-701, 11th Block,
CGO Complex, New Delhi-110003
Dated: 20th March, 2023

To,

All Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Secretaries of States/ UTs

Subject: Modification in Guidelines of DISHA Committees-reg.

Sir/Madam,

This is to inform you that the competent authority has decided to amend existing provisions of DISHA Guidelines with immediate effect. The details of the amendments are enclosed at Annexure 1. The changes are highlighted in bold.

2. It is requested that the amendments may be circulated to all Members of Parliament, State Assemblies & Legislative Councils of your State/ UT and Member Secretaries of DISHA Committees for information and necessary action. In this regard, the earlier guidelines pertaining to DISHA Committees may be viewed in the DISHA dashboard at www.dishadashboard.nic.in to facilitate understanding of the changes effectuated in their entirety.

Yours faithfully,

Kalyani Mishra

Encl: as above.

(Kalyani Mishra)
Economic Advisor

Annexure I

Proposed amendments in District Development Coordination and Monitoring Committee (DISHA) guidelines

Amendment 1:

Para 3: Composition

The District Development Coordination and Monitoring Committee (DISHA) should have the following composition:

3.1 Chairperson: The Chairperson of the DISHA should be a Member of Parliament (Lok Sabha) elected from the district, nominated by the Ministry of Rural Development. The criteria for nomination should be in the following order:

i.

i. Where there are more than one Member of Parliament (Lok Sabha) representing the district, the senior-most Member of Parliament (Lok Sabha) should be nominated as the Chairperson. The Warrant of Precedence (WoP) maintained by the Ministry of Home Affairs (MHA) should be followed **in case of MPs who have not been nominated as Chairperson in any other district**, which may result in exceptions.

ii. **In case more than one district(s) fall in same Parliamentary Constituency (Lok Sabha), the MP from the Parliamentary Constituency will become Chairperson of District(s), the area of which fall entirely in the said Parliamentary Constituency.**

iii. If the district has more than one Parliamentary Constituency (Lok Sabha) as its segments and the senior-most Member of Parliament (Lok Sabha) ***(irrespective of seniority based on the criteria of number of tenures or WoP maintained by the MHA)*** is made Chairperson of DISHA in some other district(s) (read with Note 2. below), the next senior-most Member of Parliament (Lok Sabha) should be the Chairperson.

iv. In case of same seniority, the Chairperson should be the Member of Parliament in whose Parliamentary Constituency the largest geographical area of the district falls.

Note

1. *In case the MP from RS is senior following the Warrant of Precedence maintained by the Ministry of Home Affairs, he/ she may be made as Chairperson of the committee.*
2. ***Member can be Chairperson of maximum three districts [excluding NE States, Jammu and Kashmir, Bastar (Chhattisgarh), Almora (Uttarakhand) and Mandi (Himachal Pradesh)].***
3. ***In case senior most MP (irrespective of seniority based on the criteria of number of tenures or WoP maintained by the MHA) elected from district is not Chairperson of district, he/ she shall be invited as a Special invitee by the Member Secretary in consultation with the Chairperson of the district DISHA Committee.***

Amendment 2: Relating to Nomination of Non-official members in District DISHA Committees

Following to be inserted before 3 (x)

Note: The nomination of members in the category of 3(ix) may be done by the Ministry of Rural Development in consultation with MP (LS) representing the District and MP (RS) opted for the District.

Amendment 3: (Proposed amendments in State Development Coordination and Monitoring Committee (DISHA) guidelines)

Para 3(iii) Composition:

Six MLAs to be nominated by the State Government out of which two should be from opposition parties subject to availability. **And States where State Legislative Council also exists, three Members of Legislative Council (MLCs) to be nominated by the State Government out of which one should be from opposition party subject to availability.**

Amendment 4: Relating to Nomination of Non-official members in State DISHA Committees -

Note 1: The nomination of members in the categories in 3(x) and 3(xi) may be done by the Ministry/ Minister of Rural Development in consultation with the MP (LS) and MP (RS) representing the State.

The existing content under Para 3 Note will be Note:2

* * *

जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) के दिशानिर्देशों में प्रस्तावित संशोधन

संशोधन 1:

पैरा 3: संरचना

जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की संरचना निम्नानुसार होनी चाहिए:

3.1 अध्यक्ष: दिशा का अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित जिले से निर्वाचित संसद सदस्य (लोकसभा) होना चाहिए। नामांकन के लिए मानदंड निम्नलिखित क्रम में होने चाहिए:

i.

- i. जहां जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले एक से अधिक संसद सदस्य (लोक सभा) हैं, वहां सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य (लोक सभा) को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए। जिन संसद सदस्यों को किसी अन्य जिले में अध्यक्ष के रूप में नामित नहीं किया गया है उनके मामले में गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय) के पूर्वता अधिपत्र (डब्ल्यूओपी) का पालन किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप अपवाद हो सकते हैं।
- ii. यदि एक से अधिक जिले एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (लोकसभा) में आते हैं, तो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य जिले (जिलों) के अध्यक्ष बन जाएंगे, जिसका क्षेत्र पूरी तरह से उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है।
- iii. यदि जिले में एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (लोकसभा) हैं और सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य (लोकसभा) (कार्यकाल की संख्या या गृह मंत्रालय के पूर्वता अधिपत्र (डब्ल्यूओपी) के मानदंड के आधार पर वरिष्ठता के बावजूद) को किसी अन्य जिले में दिशा का अध्यक्ष बनाया जाता है (निम्नलिखित टिप्पणी 02 के साथ पढ़ा जाए)। तो संसद के अगले सबसे वरिष्ठ सदस्य (लोकसभा) को अध्यक्ष होना चाहिए।
- iv. उसी वरिष्ठता के मामले में, अध्यक्ष वही संसद सदस्य होना चाहिए जिसके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिले का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र पड़ता है।

टिप्पणी

1. यदि राज्यसभा से संसद सदस्य गृह मंत्रालय द्वारा रखे गए वरीयता वारंट का पालन करते हुए वरिष्ठ है, तो उसे समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
2. सदस्य अधिकतम तीन जिलों [पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, बस्तर (छत्तीसगढ़), अल्मोड़ा (उत्तराखंड) और मंडी (हिमाचल प्रदेश) को छोड़कर] के अध्यक्ष हो सकते हैं।
3. यदि जिले से चुने गए वरिष्ठतम संसद सदस्य (कार्यकाल की संख्या या गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय) के पूर्वता अधिपत्र (डब्ल्यूओपी) के मानदंडों के आधार पर वरिष्ठता के बावजूद) जिले के अध्यक्ष

नहीं हैं, तो वह जिला दिशा समिति के अध्यक्ष के परामर्श से सदस्य सचिव द्वारा विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किए जाएंगे।

संशोधन 2 जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) में गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन से संबंधित

***3 (x)* से पहले निम्नलिखित सम्मिलित किया जाना चाहिए**

टिप्पणी: 3 (ix) की श्रेणी में सदस्यों का नामांकन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य (लोकसभा) और जिले के लिए चुने गए संसद सदस्य (राज्यसभा) के परामर्श से किया जा सकता है।

अनुबंध: 3 (राज्य विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) दिशानिर्देशों में प्रस्तावित संशोधन)

पैरा 3 (iii) संरचना:

राज्य सरकार द्वारा छह विधायक नामित किए जाएंगे, जिनमें से दो विधायक विपक्षी दलों से होने चाहिए, यदि उपलब्ध हों; और जिन राज्यों में राज्य विधान परिषद भी मौजूद है, वहां विधान परिषद के तीन सदस्य (एमएलसी) राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने चाहिए, जिनमें से एक विपक्षी दल से होना चाहिए, यदि उपलब्ध हों।

संशोधन 4: जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) में गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन से संबंधित

टिप्पणी 1: 3 (x) *और* 3 (xi) श्रेणियों में सदस्यों का नामांकन मंत्रालय/ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य (लोकसभा) और संसद सदस्य (राज्यसभा) के परामर्श से किया जा सकता है।

पैरा 3 टिप्पणी के तहत मौजूदा सामग्री टिप्पणी: 2 होगा